STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Yes, Sir. The issue of revising the guidelines is under consideration.

Financial assistance for tackling extremist activities

2572. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Govoernment of Andhra Pradesh has submitted a project report with a request for financial assitance for tackling extremists activities in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken to sanction and release the amount demanded?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) Yes, Sir. The State Government of Andhra Pradesh submitted a three year Action Plan for strengthening police force and development in naxalite affected tribal areas at a total cost of Rs. 1299.17 crores. The Action Plan was examined keeping in view similar problems being experienced by the State of Orissa, Maharashtra and Madhya Pradesh. The State Government will have to dovetail their existing development programmes in naxalite affected areas and approach the concerned Central Ministries for assistance under different Central schemes administered by them.

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का उपयोग

2573. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम० पी० एल० ए० डी) के अन्तर्गत आबंटित निधियों के उपयोग पर नजर रखती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सम्पन्न किये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कूरेभार क्षेत्र में नहर के साथ बनने वाली सड़क "गालिबहा-चमुरखा-सेडर-जाफरपुर सम्पर्क मार्ग" पर कार्य रोकने के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य दोबारा कब तक शुरु हो जाएगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को इस योजना के संबंध में केन्द्र के स्तर पर केन्द्रीय उत्तरदायित्व जिसमें उक्त योजना का प्रबोधन करना शामिल है, दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में जिला सुलतानपुर को रु० 700/- लाख की कुल राशि जारी की गई, जिसमें से कि रु० 551.75 लाख की राशि के कार्य को मंजूरी दे दी गई है।

(ग) और (घ) सुलतान पुर जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, गालिबहा-चमुरखा-सेडर / जाफरापुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु न तो उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, न ही विचाराधीन है।

Funds for basic minimum services in North-East

2574. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had recently announced a proposal to earmark Rs. 2000 crore over and above the Plan outlay for providing Basic Minimum Services in North-East;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the break-up of the said package for each State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2575. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं योजना के दौरान विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने आठवीं योजना के समाप्त हो जाने के बाद भी आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रत्येक ने कितनी धनराशि का उपयोग किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग): राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋण और अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है और यह विशिष्ट परियोजनाओं से संबद्ध नहीं है। राज्य के योजना परिव्यय का निर्धारण केन्द्रीय सहायता और राज्यों के अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और योजना परिव्यय के क्षेत्रक/उपक्षेत्रक/स्कीम-वार आबंटन को राज्यों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग किए गए योजना परिव्ययों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिये)**।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय / प्रत्याशित व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित परिव्यय (1991-92 की कीमतों पर)	प्रत्याशित व्यय*	प्रतिशत उपभोग
1.	2.	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10500.00	12931.00 (10,006.50)	123.15 (95.30)
2.	अरूणाचल प्रदेश	1155.00	1739.20 (1,306.92)	150.58 (113.15)
3.	असम	4662.00	4980.68 (3,761.45)	106.84 (80.68)
4.	बिहार	13000.00	5507.92 (4,201.83)	42.37 (32.32)
5.	गोवा	761.00	840.64 (641.14)	110.47 (84.25)